(III)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 30th November, 1999, adopted the following motion:-

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term ending on the 30th April, 2000, and do communicate to this House the names of the Members so nominated by Rajya Sabha."I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the Members of Rajya Sabha so nominated, may be communicated to this House."

SHORT DURATION DISCUSSION

Unprecedented supercyclone in Orissa - Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Now, hon. Members, I want the sense of the House. Should we have the reply tomorrow? It is subject to the convenience of the hon. Ministers. If they can come tomorrow...

श्री जार्ज फर्नांडीज : आज ही करा दीजिए ।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I understand that you are taking the sense of the House. Since it is past 5 o' clock, what we are given to understand is that since there is not much Government's business this week, we should have the reply tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : I was thinking that when we were insisting on speaking at length, why not hear them now? We were insisting on speaking without any time constraint.....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: We want to make it very, very clear. Had there been any urgent Government business, there would have been absolutely no problem to accommodate this situation. But, since it is already past 5 p.m., we can have the reply tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : May we have the reply of the Minister?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR) : Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : It means that the sense of the House is, we should continue.

SHRI NILOTPAL BASU: Is this the way the sense of the House is decided?

No problem. We can have different situations also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : I presume that yours is the only dissent.

SHRI NILOTPAL BASU : We accept that if this is the manner in which the sense of the house is decided, then there will be different situations also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) :There is no question of manner. Yours is the lone dissenting voice.

SHRI NILOTPAL BASU :Sir, if you are going to take the sense of the House formally, then we can have the voice vote on that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) :Mr Basu, let us continue. Yes, Mr Fernandes.

SHRI NILOTPAL BASU : Sir, with all deference to the Chair, if you say there is a significant opinion and if you want to take the sense of the House, then take it properly and decide (... *(Interruption)*...s) We do not have so much of Government Business subsequently in this week. Therefore, we are saying that there is no point of sitting beyond five today. We can have the reply of the hon. Minister tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Anybody else supporting Mr. Basu? ....*(Interruptions)*....Please continue, Mr. Fernandes.

श्री जार्ज फर्नान्डीज : : उपसभाध्यक्ष जी, अनेक माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान यह बात कही कि इस आपदा की उचित समय पर अगर जानकारी उन संस्थाओं के द्वारा मिली होती जिनका काम है यह जानकारी देना तो जो नुक्सान वहां पर हुआ है वह नुक्सान नहीं हुआ होता। उपसभाध्यक्ष जी, इसकी जानकारी यूं तो 25 तारीख से थी। यह जो आपदा हुई वह 29 तारीख को हुई लेकिन 25 तारीख से इसकी जानकारी अनेक प्रचार, प्रसार साधनों के द्वारा मिल चुकी थी और देश की जो नौसेना है वह तो समूचे देश

को अपनी बात नहीं बताती है लेकिन जिन क्षेत्रों में जानकारी जानी चाहिए उन क्षेत्रों में अपनी जानकारी देती है। असल में 26 तारीख की रात को उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने मेरे घर के फोन पर एक फैक्स भेजा था जिसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी थीं कि एक भारी तूफान आना है और हमें तत्काल आपकी मदद चाहिए। मेरे हाथ में यह फैक्स रात को साढ़े 12 बजे आया और सुबह सबसे पहले हमने सेना के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। लेकिन उन्हें इसके पहले यह सूचना मिल चुकी थी नौसेना की ओर से और 27 तारीख को सेना के जरिए और रक्षा मंत्रालय के जरिए इस पर जो जो उड़ीसा में मदद के लिए कार्यवाही की आवश्यकता थी उस दिशा में कदम उठा। 28 तारीख को सेना के कालम्स तैयार रहे और कलकत्ता तथा रांची से 29 तारीख की सुबह वे रवाना हुए। उन्हें उड़ीसा में पहुंचने में 12 घंटे से 20 घंटे लगे चूंकि 29 की सुबह जो तूफान आना था उसके चलते उनके रास्ते में जहां-जहां पेड़ गिरे थे, रुकावटें थीं - अनेकों प्रकार की रुकावटें थीं - उन रुकावटों को दूर करते उनको उड़ीसा जाना पड़ा। 29 तारीख को जो हुआ वह तो सभी लोगों के ध्यान में है। 30 तारीख को वहां जाने का प्रयास हमने किया। हमारे साथ गृह मंत्री थे, उड़ीसा के हमारे मंत्रिमंडल के दो मंत्री थे। श्री नवीन पटनायक जी और श्री जेओलो राम जी भी हमारे साथ थे । लेकिन हम लोग कलई कुंड से आगे नहीं जा पाए और वहां भी उतरना उस दिन बहुत कठिन काम था । एक तारीख को हम लोग उस तरफ गए । हम दोनों थे और जेओलो राम भी थे । पारादीप में उतरना संभव नहीं था, लेकिन नियम के बाहर जाकर हम ने उस पायलट को उतरने के लिए कहा । हम उतरे, वहां की परिस्थिति को समझा, कुछ अनुभव किया और तब तक मात्र सेना नहीं बल्कि वायु सेना और नौ-सेना भी काम में लग गयी थीं । जब हम पारादीप में थे तो एक मायने में बंदरगाह बिल्कुल ही खत्म हो चुका था और किसी भी जहाज का अंदर घुसना संभव नहीं था, लेकिन उस के बाहर समुद्र में नेवी के पांच जहाज थे जिन में से तीन जहाजों में राहत सामग्री थी और लोगों के खाने आदि की जो भी चीजें इतनी जल्दी में वहां पहुंचाना संभव था, वह सब थीं । विशाखापतनम् से वह जहाज वहां पहुंचे थे और केवल राहत तक ही उन का कार्य सीमित नहीं था बल्कि उस बंदरगाह में जो भी नुकसान हुआ था, उस नुकसान से बंदरगाह को बाहर निकालने और वह काम के लायक बने, इस दिशा में उन की ओर से जो प्राथमिक कार्य होने चाहिए थे, उस कार्य में नौ-सेना के जहाज लगे हुए थे ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं ने यह बात विस्तार से सदन के सामने रखी क्योंकि एक बात यहां बार-बार कही गयी थी कि केन्द्र सरकार बिल्कुल ख्याल ही नहीं कर रही थी, उस का ख्याल है ही नहीं । तो जिस क्षण से वह सूचना मिली थी, उसी क्षण से जो ख्याल देना

शुरू किया है और उस में किसी प्रकार की कमी इस क्षण तक नहीं हुई है।

महोदय, क्या-क्या हुआ है उस पर मैं आगे जाऊंगा, लेकिन एक बात जो वहां की नौकरशाही के बारे में यहां सुनने को मिली और बाहर भी सुनने को मिलती है, उस पर दो शब्द मुझे शुरू में कहने हैं । महोदय, हम सभी लोग मानते हैं कि यह एक भारी हादसा हुआ है ...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JASWANT SINGH) : Mr. Minister, could I intervene for a while? Sir, I want to take this opportunity -- because my good friend, the hon. Minister of Defence has been reticent about this aspect -- and I do wish to, in all responsibility and seriousness, place on record the excellent work done by the armed forces, particularly the Indian Navy, which reached Paradeep when the weather condition there was such which made it impossible to reach the place, and the alertness and alacrity with which Paradeep Port was cleared, within hours of the severe cyclone. Because this has not featured in either of the two Houses, I thought I would interrupt my friend and place on record this act of supreme heroism by the vessels of the Indian Navy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Thank you, Mr. Minister. We take a grateful note of it.

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपसभाध्यक्ष जी, नौकरशाही के बारे में एक बात कही जा रही है कि वह काम नहीं कर रही है या काम नहीं कर पाई या उन से जो भी अपेक्षाएं थीं उन्हें वह पूरा नहीं कर पाई । महोदय, एक तरफ हम लोग ही कह रहे हैं कि डेढ़ करोड़ लोग इस विपदा में फंसे, उन पर इस का प्रभाव पड़ा और उन्हीं के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं । उपसभाध्यक्ष जी, वह जो डेढ़ करोड़ लोग हैं, वह आख़िर उड़ीसा के ही एक हिस्से के लोग हैं और उस में 14 जिले भी आते हैं । उन 14 जिलों के जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह राज्य स्तर के हों, जिला स्तर के हों या पंचायत स्तर के हों, वह भी तो इस के शिकार बने हैं । और हम भूल जाते हैं कि इस हादसे के जो जो व्यक्ति शिकार हुए हैं, उनमें सरकारी नौकरों की संख्या भी है, हर वर्ग के सरकारी नौकरों की संख्या है क्योंकि इस सदन में कुछ सदस्यों ने इस बात को कहा । वहां जो पानी उभर कर आया था उसकी जो ऊंचाई थी, उस ऊंचाई के पानी ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को भी बचने का मौका नहीं दिया और आज वहां जो एक प्रकार से लोग निराश्रित होकर पड़े हुए हैं, जिनकी संख्या लाखों में हैं, उनमें भी सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके परिवार भी हैं । इसलिए जो हम सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ग विशेष मानकर चलते हैं, तो वह भी एक

नागरिक हैं उड़ीसा के उस इलाके के, जहां पर यह हादसा हुआ और यह सारी परिस्थितियां बनीं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं । हम चाहेंगे कि इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखें । हां, जो चीफ सेक्रेटरी चला गया छुट्टी लेकर, उनको जिन लोगों ने इजाजत दी जाने के लिए, उनके ऊपर आप जरूर बरसिए । उसमें किसी का कोई विरोध नहीं होगा । लेकिन, समूचे उड़ीसा के इन कर्मचारियों पर उंगली उठाना उनके साथ अन्याय होगा । हम चाहेंगे कि हम अपनी बहस के दौरान और इस मामले की सोच के दौरान इस बात को जरूर ध्यान में रखें ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा, सबसे पहले जो भी राहत और बचाव का काम जिसने किया, वह सेना ने किया, सेना के साथ तीनों, थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने किया और नौसेना में यह भी जोड़ना जरूरी है विशेष तौर से कि कोस्ट गार्ड, क्योंकि कोस्ट गार्ड का काम वहां पर कुछ कम नहीं रहा। जैसा कि जिक्र अभी यहां पर माननीय जसवंत सिंह जी ने किया, वह लोग वहां पर पहले से थे और नेवी यह जानते हुए वहां पहुंची थी कि यह तूफान पारादीप पर हमला करने वाला है । इनके साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी के लोग वहां पहुंचे, बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन के लोग गए, एनसीसी के लोग वहां पहुंचे और रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो भी किसी भी क्षेत्र के लोगों को जो भी मोबलाइज किया जा सकता था, जिसमें हमारे डीआरडीओ के लोग भी गए, साइंटिस्ट भी गए और रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो भी किसी भी क्षेत्र के लोगों को जो भी मोबलाइज किया जा सकता था, इन सब लोगों ने वहां सबसे पहले जाकर काम करना शुरू किया, खाना जहाजो से, हेलीकाप्टर से गिराने से लेकर लोगों की जान बचाने तक का काम किया । वहां एनजीओस भी बड़ी संख्या में गए, हमने वाल्युंटरी आर्गेनाइजेशन का काम जीवन भर देखा है, किया भी है, लेकिन उड़ीसा में उनका जो काम देखा है उसका तो कोई जवाब नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम आखिरी बार अभी चार-पांच दिन पहले वहां गए थे । वहां अरखामा के छोटे छोटे गांवों में हम गए । वहां अभी भी लाशें हैं, आज के दिन भी हैं और जिनको निकालने में समय लग जाएगा । यह बात सभी लोग मानते हैं । यह इसलिए है कि वहां पर पानी भरा हुआ है और जब तक वह पानी पूरा उतर नहीं जाता, तब तक पता नहीं चल पाएगा, ऐसा सब का मानना है ।

उपसभाध्यक्ष जी, यहां दिल्ली से महानगर पालिका के कर्मचारियों को वहां जाना पड़ा लाशें उठाने के लिए, मुम्बई महानगर पालिका से पांच सौ कर्मचारी गए वहां लाशें उठाने, और लोगों ने भी उठाई होंगी, मगर इनको विशेष तौर से उसी काम के लिए वहां पर भेजा

गया था । लेकिन, जिनको नहीं भेजा गया था, जिन्होंने स्वेच्छा से वहां जाकर काम किया सबसे अधिक लाशें उठाने का, उनमें आनंदमार्ग और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भारी काम रहा । उनका केवल लाशें उठाने तक का काम नहीं रहा, राहत कार्य का भी उनका काम रहा । देश भर से वहां स्वयं सेवी संगठन गए । उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोई भी भाग नहीं बचा, जहां से लोग वहां न गए हों । राज्य सरकारों का भी योगदान बहुत अच्छा रहा है । किसने कितना भेजा, वह समय जब आ जाएगा हिसाब लगाने का, तब हिसाब लग जाएगा लेकिन आन्ध्र प्रदेश ने पहल की और उनकी गाड़ियां अंदर घुस नहीं पाई थीं क्योंकि सड़कें चलने लायक नहीं थीं, पेड़ गिरे हुए थे, सबसे शुरूआत में उनकी मदद रही । अब उस पर यहां बहस भी हो गई कि कोई बिल वगैरह भेजा है । कुछ चीजें उड़ीसा की सरकार ने दूसरों से मांगी हैं, जो उनके अपने खजाने में नहीं हैं, जो बाहर से लेकर भेजनी पड़ती हैं, उदाहरणार्थ बैल चाहिए, चारा चाहिए । खेत के लिए बैल की जरूरत है, जानवरों के लिए वहां पर चारे की जरूरत है और यदि वह प्रदेश में नहीं है तो बाहर से मंगाना पड़ता है और कोई सरकार यदि दान के तौर पर दे सकती है तो दे, लेकिन खरीदकर भेजती हो तो जरूर बिल जाएगा । यूं तो केन्द्र सरकार, विशेषकर रक्षा विभाग के जो भी लोग जाते हैं तो वे भी अपना हिसाब रखते हैं कि कितना पैट्रोल खर्च हुआ, कितनी अलग-अलग सामग्री खर्च हुई, लेकिन आम तौर पर बिल नहीं भेजते हैं ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे ही राज्य सरकारों ने भी जो काम किया, मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के वहां पर डाक्टर हैं, इस क्षण हैं , मुम्बई महानगर पालिका के कर्मचारियों को वहां भेजने के लिए जो गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा था, उनको काम करने के लिए जो सामान वगैरह भेजने के लिए जो ट्रक लेने पड़े, वे महाराष्ट्र सरकार ने किराए पर लिए, उसके खर्च का कोई बिल नहीं भेजेगा और महाराष्ट्र सरकार ने और भी वहां पर काम के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है, कुछ गांवों को अपने जिम्मे लेने की बात ही नहीं, कुछ और आगे जाकर भी उन्होंने अपना योगदान वहां दिया । पंजाब सरकार का काम भी बहुत बढ़िया काम रहा है । एक पूरी रेल परसों उन्होंने भेजी यहां से कम्बलों से भरी, नए कम्बलों से भरकर । उससे पहले एक दिन एक हवाई जहाज भरकर सामान भेजा और उससे पहले ट्रकों से जितना सामान संभव था, वह भेजा और एक लाख लोगों के लिए वहां पर आज के दिन भी लंगर चल रहा है और 300 वालेंटियर्स पंजाब सरकार ने वहां पर भेजे हैं और यहां पर किसी ने कोई दल का, कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार, ऐसी चीजों का किसी ने ख्याल नहीं किया । सारा देश एक साथ खड़ा हुआ है उड़ीसा की इस आपदा में उड़ीसा के लोगों की मदद के लिए ।

उपसभाध्यक्ष जी, अंदाज़न, मैं अभी इसलिए अंदाज़न कहता हूं कि मेरे पास अभी

इसका जो आखिरी आंकड़ा है अधिकृत, वह 19 तारीख का है, जब एक लाख चालीस हजार टन खाने-पीने की वस्तुएं कपड़े, दवाइया आदि भुवनेश्वर पहुंच चुका था । यह सरकारी आंकड़ा है, प्रदेश सरकार का आंकड़ा है और जिस मात्रा में उसके बाद भी भेजा जाता रहा, हमारा अंदाज़ा है कि आज के दिन दो लाख टन से कम सामग्री वहां पर नहीं पहुंची है आज तक । बंटवारे की बात कोई पूछे, तो मैं उस पर कुछ स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारी इच्छा थी कि वहां पर सेना बनी रहे । पांच हजार जवान थे हमारे इंजीनियरी विभाग के, दवाई विभाग के, सड़क आदि का इंतजाम करने वाले और इन्फेंट्री के, कुल मिलाकर पांच हजार हमारे जवान रहे । एक मेजर जनरल को विशेष इस काम के लिए हमने भुवनेश्वर भेजा और उनके नीचे पूरे उनके कमांड स्ट्रक्चर के सारे अधिकारी बने रहे, लेकिन मेरे ख्याल से 15-16 तारीख को बताया गया कि अभी उनको कुछ जिलों से निकाला जाना चाहिए । मैंने मुख्य मंत्री से बात की और कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो ? कानून-व्यवस्था का प्रश्न भी अपनी जगह है, सामग्री आ रही है, इसके बंटवारे का काम भी है । मैं जानता हूं कि लोग बहुत हैं लेकिन सेना के रहने से कुछ उसका दबदबा भी बना रहेगा और कोई गलत काम भी नहीं हो पाएगा । तो वे बोले कि हम उनको नहीं जाने देंगे । लेकिन वह ऑर्डर ज्यों का त्यों रहा और दो-चार दिन के बाद एक और ऑर्डर निकला कि कुछ और भी जगहों से जाना चाहिए और अब इस समय बीते कल से सिवाय जगतसिंहपुर में और कहीं सेना नहीं है और वहां भी केवल हमारी एक मेडिकल यूनिट है और टैरिटोरियल आर्मी की एक छोटी कंपनी छोड़कर अब वहां कोई सेना नहीं बची है । राज्य सरकार ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है । इसलिए वहां किस तरह से बंटवारा हो रहा है, इन चीजों के बारे में अगर केंद्र के ऊपर कोई अंगुली उठाता है तो उपसभाध्यक्ष महोदय, हम उसमें कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं ।

महोदय, यहां एक सदस्य ने पूछा कि क्या आपको, केंद्र को कोई ऐसा अधिकार है ? अगर अधिकार होता तो हम सेना को बाहर क्यों लाते ? राज्य सरकार जब कहेगी कि यहां पर सेना रहनी चाहिए, तभी वहां पर सेना रहेगी । जब राज्य सरकार कहेगी कि चले जाइए तो वह निकलकर आ जाएगी और निकलकर आई है । वहां जो आवश्यकताएं हैं, तात्कालिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए और आवश्यक चीजों को पहुंचाने में अभी हमने जिन-जिन लोगों का जिक्र किया, उन सबका योगदान रहा है । महोदय, समूची नेवी में काटकर हमारे करीब 55,000 नाविक और अधिकारी हैं, उन लोगों ने अपनी एक दिन की तनख्वाह पहले ही दिन भेजी और यही काम सेना ने भी किया है, औरों ने भी

किया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राहत का जहां तक प्रश्न है, हम यह मानते हैं, टास्क-फोर्स के नाते भी मानते हैं और एक नागरिक होने के नाते भी मानते हैं कि वहां आज भी खाने की वस्तुओं की, पीने के पानी की, दवाइयों की, कपड़ों की और अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है । अब यह हो सकता है कि जितनी सहायता चाहिए उतनी भुवनेश्वर के स्टेडियम में, कलक्टर के दफ्तर के बाहर और दूसरे कंपाउंड्स में पहुंची हो लेकिन उसका बंटवारा होना भी जरूरी है और लोगों को इस सहायता की आज भी जरूरत है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि अभी ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पहुंचना संभव नहीं है । यह बात सही है । हम लाशें भी निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी अभी भी उन इलाकों में है । तो इस बात को दोहराने की कोई विशेष जरूरत नहीं कि अनेक ऐसे इलाके हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, हम लोगों को अपने को यहां से आगे बढ़ाकर सोचना चाहिए और इस दिशा में राज्य सरकार ने पहल की है और केन्द्र सरकार ने भी पहल की है । इस कार्य के लिए जो टास्क-फोर्स प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, उसका अपना ही योगदान है ।

महोदय, राज्य सरकार ने 19 तारीख को मुझे एक दस्तावेज़ दिया है । उसमें उन्होंने क्या-क्या चीजें वहां पर चाहिए शॉर्ट-टर्म या तात्कालिक और इमीडियेट मीडियम टर्म बताई हैं - emergency relief, exgratia assistance to the bereaved families, temporary shelter, clothing and utensials, चूंकि वहां पर कुछ भी बचा नहीं है, cattle/animal care, house building assistance, कोई पक्के मकान तो नहीं लेकिन फिलहाल सर छिपाने के लिए मकान बनाने हैं, supplementary nutrition to support children and indigent, assistance to fishermen families, support for Rabi programme, emergent requirement for drinking water, emergency repair, restoration of critical infrastructure like schools, health centres, roads of a temporary nature, emergency restoration of irrigation systems to support Rabi programme, additional requirements for Ganjam cyclone victims and health measures. कुल मिलाकर उन्होंने जो मांग की है या जो आपने अंदाज़ भेजा है कि इतना पैसा उनको चाहिए, वह 657 करोड़ रुपए का है । इस 657 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ रुपए का पहले ही प्रधान मंत्री ने ऐलान किया था और वह पैसा नेशनल फंड फॉर केलेमिटी रिलीफ से दिया था । उसके बाद मुख्य मंत्री दिल्ली आए और प्रधान मंत्री से भी मिले, हमसे भी मिले और जब वित्त मंत्री से मिले तो वित्त मंत्री ने 300 करोड़ रुपया और तत्काल रिलीज़ किया । तो कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपया नेशनल फंड फॉर केलेमिटी रिलीफ से मिला लेकिन पैसा निकाला अलग-अलग मदों से क्योंकि नेशनल फंड फॉर

केलेमिटी रिलीफ में पैसा नहीं है, एक रुपया नहीं है । तो इसलिए पहले से यह बात मुख्य मंत्री को भी बताई थी, उनके दल के नेता जब प्रधान मंत्री से मिलने आए थे तो उन्हें भी बता दी थी कि नेशनल फंड जो है, वह खाली हो चुका है । वह फंड तो खाली हो चुका है । वह फंड 700 करोड़ रुपए का होना था 1995 से 2000 तक । जिस फाइनेंस कमीशन का हवाला यहां पर बार-बार दिया जाता है, उस फाइनेंस कमीशन की जो रिकमंडेशन थी कि नेशनल केलेमिटी रिलीफ फंड नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में यह कन्फ्यूज़न है कि इस फंड का नाम नेशनल केलेमिटी रिलीफ फड है इसलिए नेशनल केलेमिटी इसको कहा जाए, डिक्लेयर किया जाए तब यह पैसा मिल सकता है, ऐसी एक समझ है और यह समझ हर स्तर पर है । कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने प्रधान मंत्री को लिखे हुए पत्र में यह बात लिखी है, मैं इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं कि कोई टिप्पणी करूं या इसके प्रति कोई गलत बात यहां पर कहूं बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि यह गलतफहमी है । उनके पत्र में उन्होंने लिखा है कि ऐसी घोषणा करने पर हमें पैसा मिलेगा उस एजेंसी से जिसका नाम है नेशनल केलेमिटी रिलीफ फंड । मगर नेशनल केलेमिटी रिलीफ फंड से पैसा वह घोषणा करने पर भी मिलने वाला नहीं है । जिस बात को बार-बार यहां पर छेड़ा गया और बार-बार इसको पढ़ा गया.....(व्यवधान).....

SHRI JIBON ROY: But what is the problem in declaring it as a national calamity? ....*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE FERNANDES : I will tell you the problem. ....*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष जी, मुझे परेशानी एक बात की है कि किसी ने एक दस्तावेज़ का.....(व्यवधान).....

SHRI NILOTPAL BASU: If you just yield for a moment, our question is ....*(Interruptions)*.... What we were interested to know is, out of this total money, how much is the grant, and how much is the loan.

SHRI GEORGE FERNANDES: I have already made this clear. First, Rs. 200 crores were given, and then Rs.300 crores were given. So, Rs.500 crores have been given. It is not a grant. It is considered as a relief from the National Fund for Calamity Relief. ....*(Interruptions)*... There is another amount of 450 crores of rupees which have, in advance, been made available against the Plan expenditure, with a statement from the Finance Minister that "Please spend the money, there will never be shortage of money insofar as relief is concerned." This has repeatedly been made known times. Not once,

not twice umpteen times और इसके बावजूद जब यह बात चलाई जा रही है क्योंकि इस समझ के चलते Most important, I would appeal to you to declare the super cyclone of the millennium as a national calamity of rare severity. और अगला वाक्य है उपसभाध्यक्ष जी, This would make the State eligible for a greater grant from the National Fund for Calamity Relief. और यहां पर भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दुनिया भर से पैसा आ जाएगा यह घोषणा करने पर । किसने कहा ? लातूर में इतना बड़ा भूकंप आया, दस हज़ार से अधिक लोग मरे, दो लाख से अधिक मकान गिरे । वर्ल्ड बैंक से 1200 करोड़ रुपया कर्ज के तौर पर आया। उसको केन्द्र सरकार ने लिया, एक प्रतिशत ब्याज पर केन्द्र सरकार को पैसा मिला। केन्द्र सरकार ने वह पैसा महाराष्ट्र सरकार को , मैं शायद ठीक नहीं कह पाऊंगा, छह प्रतिशत या आठ प्रतिशत ब्याज पर महाराष्ट्र सरकार को दिया। बीस साल से चालीस साल में उसे वापस करना है और आज के दिन उड़ीसा के लिए अगर हम लोगों को वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है, और हमें लेना है, उसके लिए केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मगर इसके लिए सबसे पहले प्रदेश की सरकार को जो नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा देना जरूरी है। हमारे लिए नहीं, केन्द्र सरकार के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड बैंक को देने के लिए। जिस पर फिर वर्ल्ड बैंक अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेगा, जांच करेगा और उसके बाद वह पैसा आ जाएगा और वह पैसा एक प्रतिशत ब्याज पर आ सकता होगा तो एक प्रतिशत ब्याज पर लाने का प्रयास होगा। जैसा इसके पहले हुआ है। मगर यह समझना होगा कि बाहर से पैसा आने के लिए ऐसा ऐलान होना जरूरी है उपसभाध्यक्ष महोदय, इसका कोई रिश्ता नहीं है। यूनिसेफ के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। पैसा लेकर काम कर रहे हैं, केयर के लोग वहां आकर काम कर रहे हैं। ये सब विदेशी संस्थाएं काम में लगी हैं। बाहर से पैसा आ रहा है। भारत सरकार ने यह नहीं कहा है कि पैसा नहीं आए। यह जरूर कहा है कि जो पैसा आएगा उसको विदेश मंत्रालय के द्वारा Nodal Ministry will be the Ministry of External Affairs. जो हमेशा होता है। उसमें कोई नयी चीज नहीं कही है। सैकड़ों-करोड़ों में विदेश से एन.जी.ओ. के लिए पैसा आता है। वह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो उसी तरह से यहां पर यह कहा गया है कि पैसा इस तरह से आ जाएगा और पैसा आ रहा है, संस्थाए आ रही हैं और यह जो गलतफहमी फैली है इसको हम निकालना चाहते हैं। I am not getting into a hair-splitting debate मैंने कहा कि इस दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक वाक्य पढ़ेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। उपसभाध्यक्ष जी, एक वाक्य से इसका अर्थ नहीं होगा। नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था और टैंथ कमीशन ने क्या कहा था। नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने

एक ही काम किया था केलामिटी के बारे में और उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक प्रदेश का फण्ड रहेगा और हर प्रदेश अपना फण्ड बनाएगा जिसमे केन्द्र 75 प्रतिशत योगदान देगा और वह प्रदेश 25 प्रतिशत देगा। किस प्रदेश का कितना होगा वह उस प्रदेश को तय करना चाहिए। इसके पहले के अनुभव, ऐसा हादसा और ऐसी आपदाओं , ये सब चीजें ख्याल में रखकर वह प्रदेश को तय करना चाहिए। जैसे पूर्वांचल के प्रदेश में इस प्रकार की कोई परेशानी कभी नहीं आई है। तो इसलिए वह नहीं भी करे - किसी को फण्ड करना हो तो 50 लाख का करे, नाम के लिए करे। यह नाइंथ फाइनेंस कमीशन का प्रस्ताव था और उसके मुताबिक फण्ड बना। अनेक प्रदेशों ने अपना फण्ड बना दिया, बहुत कम फण्ड, लेकिन बना दिया। टैंथ फाइनेंस कमीशन का क्या कहना है - 9.16 , सबके हाथ में यहां पर है लेकिन पूरा पढ़ लीजिए 9.16 पैराग्राफ लास्टली, इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा है, चूंकि केलामिटी इसका टाइटिल है- Lastly, in paragraph 9.16, it is mentioned that we should consider how to deal with a calamity of rare severity. Between June, 1990 and May, 1993, the Central Government is reported to have received 30 memoranda from the States seeking additional Central assistance, on the ground that they had experienced a calamity of rare severity. None was declared, Sir. None. While it is no doubt true that the country has been spared the agony of the type witnessed during the severe droughts of 1986-87, 1987-88, nevertheless, floods and drought of varying intensity and magnitude have continued to be experienced in various parts of the country almost every year. From time to time, calamities of such a severity may occur in various regions which the States may not able to manage with their own calamity relief fund. They continue: ""At such times, the Central Government must be in a position to come to the rescue of the State and organize relief on a national scale."

In the next para, they say:

We have considered the issue carefully and are of the view that a calamity of rare severity would necessarily have to be adjudged on a case-to-case basis, taking into account, inter alia, the intensity and magnitude of the calamity, level of relief assistance needed, the capacity of the State to tackle the problem, the alternatives and flexibility available within the Plans to succour and relief etc."

Sir, this is the crucial sentence:

""Any definition bristles with insurmountable difficulties and is likely to

be counter-productive."

The Finance Commission has said that you cannot define it. There is no question of defining it. Therefore, there is no question of a declaration. You have to treat a cyclone as one of rare severity.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Is it not hair-splitting on the part of the Minister? What is the argument of the Government?

SHRI GEORGE FERNANDES: This is not hair-splitting, Sir.

SHRI JIBON ROY: You do politics in politics. ....*(Interruptions)*... You do politics in the super cyclone also. You are a good politician! ....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Let us hear him.

SHRI JIBON ROY: We are hearing him patiently.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Let us continue with our patience, please. ....*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: You speak on what will happen to Orissa, on what you want us to do, on what you want the States to do and on what you want the people to do. Polemics is enough.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Please. Thank you. Let us not have ....*(Interruptions)*... I understand your anxiety. He is giving a reply.

SHRI JIBON ROY: We are discussing this tragedy. We are not discussing about a battle between two sides.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Nobody is battling. Not a word has been said about it.

SHRI JIBON ROY: He is doing that. What else is he doing?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: If this is not hair-splitting, what is it?

.....*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE FERNANDES: I am not indulging in any hair-splitting, Sir. I am reading from the Finance Commission Report. A number of hon. Members have read it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : I request Members kindly not to interrupt. ....*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Mr. Venkaiah Naidu had set the tone. The Minister is spoiling the whole atmosphere of the House. I must say that Mr. Venkaiah Naidu had set the tone for the whole House. What is the Minister talking now? He is indulging in the hair-splitting. He is talking about severity and non-severity. What else is it?

SHRI NILOTPAL BASU: This is not the approach. The whole thing should be depoliticised. ....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Would you not like the hon. Minister to give a reply uninterrupted? Please, please. ....*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: He is not talking on the cyclone.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : First you were not willing to sit through, and now you don't want to hear him. Please, please. ....*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: There is no humanitarian approach.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): We are listening to the hon. Minister. ....*(Interruptions)*...

We can understand it. He is arguing so much.

SHRI JIBON ROY: My State has sent Rs.10 crores. He is not mentioning that .....*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I hope the hon. Defence Minister, upholding the highest tradition of this House and the parliamentary system, will kindly look into the problem from the angle of humanitarianism. But the argument that he is advancing, I am sorry, Sir, smacks of something else than humanitarianism.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: You are not correct. The Defence

Minister is referring to the Report of the Ninth Finance Commission. ....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Please, please. We had a very peaceful debate. Let us continue with it. ....*(Interruptions)* ..

SHRI NILOTPAL BASU : Sir, some Members are allowed to speak for hours. But when we overshoot by one or two minutes, we are interrupted. We know all these things. You are taking the sense of the House on a simple question of how long the House should sit. But, this is a very wrong tradition that is being set here. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : I understand whom you are trying to target.

SHRI JIBON ROY : Sir, we want to know what does the Central Government expects from the State Governments. We as Members of Parliament want to know what do they expect.

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : प्लीज, प्लीज .....**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपसभाध्यक्ष जी, सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर .....**(व्यवधान)**

SHRI NILOTPAL BASU : The tragedy is that this should not be the situation.

SHRI S. R. BOMMAI (Karnataka) : If the hon. Minister yields, I would like to say one thing. The recommendations of the Ninth Finance Commission are in disupte. Many State Governments have opposed creating this calamity fund. The Sixth, the Seventh and the Eighth Finance Commissions had recommended different things. The Ninth Finance Commission has deviated from the previous Finance Commissions' recommendations. This itself is in dispute under dispute. Many State Governments have opposed it. Let us not spend more time on that.

SHRI GEORGE FERNANDES : I am quoting from the Tenth Finance Commission. Noth the ninth. ....*(Interruptions)*...उपसभाध्यक्ष जी, यह बोलने के लिए इसलिए जरूरी था कि .....**(व्यवधान)**

SHRI S.R. BOMMAI : Sir, I would like to know from the hon. Minister as to what is the difficulty and disadvantage in declaring it as a national calamity....(... *(Interruption)*....)..

श्री संध प्रिय गौतम : हर वक्त बोलते रहते है, आप हर वक्त बोलते रहते हैं.....(व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु : जब बोलने की जरूरत पड़ती है तभी बोलते है ।

श्री संध प्रिय गौतम : क्या आप लोगों के पास बोलने क लिए कोई सेंसिबल प्रश्न है....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : We had a very dignified debate. Let us not spoil it. (....*(Interruption)*....s) I appeal to your good sense not to spoil it. If we are dissatisfied....(....*(Interruption)*....s)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Kindly appeal to the hon. Defence Minister to restrain his language. Non declaration of national calamity of rare severety ....*(Interruptions)*...

6.00 P.M.

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपसभाध्यक्ष जी, यहां बार-बार हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगाया हैं....**(व्यवधान)** और पच्चीस तारीख को मंत्री महोदय उड़ीसा की एक विशेष मुलाकात में बोले हैं कि .....(व्यवधान) some other house ....*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम : आपकी सरकार बनने वाली तो है नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ......(व्यवधान) यह हमारे ऊपर आरोप है कि इसको नेशनल केलेमिटी घोषित नहीं कर रहे है, यह हमारे ऊपर आरोप है और हम इसका जवाब इस सदन में भी न दे।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : You can make this speech in Orissa. You can go there and make speeches there. This is a national calamity of the nation and by not following the recommendations of the Tenth Finance Commission, injustice has been done to the people of Orissa.

श्री जार्ज फर्नान्डीज :उपसभाध्यक्ष जी, टेंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का यहां पर कई सदस्यों ने जिक्र किया। कई ने पढ़कर सुनाया और कई बिना पढे ही

बोले.....(**व्यवधान**) अगर हम टेंथ कमीशन ने क्या लिखा है इसको पढ़कर सुना दें तो वह पोलिटिक्स हो जाएगा जबकि लोग इसको पढ़ रहे हैं। यह पोलिटिक्स नहीं है .....(**व्यवधान**)

श्री नीलोत्पल बसु: प्लीज, प्लीज.... आप नीतीश जी को बोलने दीजिए....वे संभाल लेंगें.....(**व्यवधान**) Let us not spoil the atmosphere.

SHRI S.R. BOMMAI : He is unnecessarily spoiling the atmosphere in the House. We did not discuss it on party lines at all. The whole discussion was at other level. I am afraid, the whole atmosphere is being unnecessarily spoild. Someone else should intervene. Either the Leader of the House or Shri Nitish Kumar. I request the Leader of the House to please intervene. He is unnecessarily spoiling the atmosphere.

SHRI JIBON ROY : He does not understand the difference between politics and cyclone.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Sir, I am on a point of order. He did not refer to Orissa. ....*(Interruptions)*... You cannot do it. You are not in the Opposition. You are a Minister. Behave like a Minister. He is spoiling the atmosphere of the House.

SHRI JIBON ROY : We want to support the Government. We want to help the Government.....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I am again appealing to you, it will give an impression that you don't want to hear the reply of the Minister. Let us not give that impression. If he is going.....*(Interruptions)*.... One minute. May I hear his suggesion?

SHRI J. CHITHARANJAN : It is unfair to say that we are not prepared to listen to the Minister. We are listening to the Minister. There is a demand raised by various political parties that the super-cyclone which devastated coastal districts of Orissa on 29-30 October, 1999 should be declared as a national calamity. He is arguing at length to say that all those who raised that demand are in a myth and are in confusion. He is the only one man who is not having any confusion. I would like to know why he is refusing to declare it as a national calamity?

SHRI GEORGE FERNANDES : There is no provision for declaring it as a national calamity.

SHRI J. CHITHARANJAN : If there is no provision for declaring it as a national calamity, you should find a remedy for that.

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपसभाध्यक्षजी, प्रधान मंत्री जी ने पहले दिन से इस बात को कहा है कि हम इसको नेशनल कैलामिटी की रेयर सेवियरिटी करके मानते हैं ....**(व्यवधान)** बोले हैं.....लिखित स्टेटमेंट है और हम सब लोग बोले हैं, रोज बोलते हैं ....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please continue.

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपसभाध्यक्षजी, अब प्रश्न यह है .....**(व्यवधान)**

श्री जीवन राय: क्या करना चाहिए, यह मेहरबानी करके बताइए....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Are you going by how it is being termed or how it is being tackled? Let us hear him. If the hon. Prime Minister has stated that it will be treated as a national calamity, then, whether it is being termed ....(....*(Interruption)*....s).. Please don't worry about that. If you have got any grievance about the manner in which . ....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU : We never differed on this. The point is, he should not refer to people who are not present in the House to defend their position. We are attempting to have a debate and a discussion in a manner where there will be no ....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): There should be no derogatory reference to a person who is not present in the House. Not otherwise.....*(Interruptions)*.... Let us hear him.

SHRI OSCAR FERNANDES (Karnataka) : We whould like to know whether the Government is declaring it as a national calamity or not. This is the simple question.

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपसभाध्यक्षजी, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि नये मंत्रिमंडल की पहली बैठक जिस दिन हुई उस दिन कैबिनेट की ओर से यह कहा गया कि This is a national calamity of rare severity.

SHRI OSCAR FERNANDES : We want the Government to declare it as a national calamity.

SHRI GEORGE FERNANDES : Under what law we should declare it so? It is not just like declaring an emergency.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Will you kindly tell me which is that provision under which you want the hon. Minister to declare it as a national calamity? I will request the Minister to consider that. Otherwise, I cannot say that there should be declaration to that effect.

श्री सनातन बिसि (उड़ीसा): आपने जो बोला है उसी का प्राविजन में बोल रहा हूं। वह चीज नहीं बोली है। वह पैराग्राफ 9 एट पेज 44 में है। उसको इंटरप्रेट किस ढंग से करेंगे वह उनकी बात है

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Which one are you reading?

SHRI SANATAN BISI: I am reading from the report of the Tenth Finance Commission. The Minister has read only one paragraph. "Once a calamity is viewed to be of rare severity, it really ought to be dealt with as a national calamity requiring assistance and support beyond what is envisaged in the CRF scheme."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Therefore, there is a clear distinction in law as to what is 'deeming' and what is a 'declaration'. 'Deeming' means perception of the Government, that they perceive it in a particular manner which they have already said. Where is the declaration? Now, let us go to the substance and not to the words.

SHRI SANATAN BISI: Sir, I wanted that they must clarify all these things. My demand was that. They must clarify so far as the recommendations of the Ninth and Tenth Finance Commissions are concerned.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : That is what the hon. Minister is doing to the best of his ability. Let him complete.

SHRI JASWANT SINGH : Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission, I would say this. This is really a sterile and pointless controversy. The hon. Defence Minister has quite clearly stated the position. If no other utterance be referred to, he has remarked that the very first meeting of the Cabinet dealt only with Orissa. The Cabinet, in its discussions, called the Orissa tragedy 'a calamity of rare severity'. It is a national calamity. This was

announced on the conclusion of the Cabinet meeting itself, on the very first day. Every day, after that, on a number of occasions, the hon. Prime Minister has stated exactly that, that it is a calamity of rare severity, national calamity of rare severity. Every action that the Union Government has taken thereafter is treating it as a national calamity of rare severity. All assistance has been provided to the State of Orissa by all agencies of the Central Government. Now, I do not know, therefore, on what point we needlessly seem to be agitated. I would request, therefore, when it comes to what it is deemed or treated as, how it is being tackled and on the aspect of the financial assistance provided as grant by the Central Government, let at least that part of it be over, so that my distinguished colleague, then, can refer to....(....*(Interruption)*....s). Let that be over.

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उन के मुंह से सुनकर समाधान हो गया ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Now, I think we are happy. Can we continue? I am grateful to the Leader of the House that he could convince you, which I could not.

श्री दीपांकर मुखर्जी : हमारी दोनों की लेंग्वेज एक है । गेट मीटिंग में बोलने की आदत उन की भी है और हमारी भी है, इसलिए वह बैटर है ।

SHRI H. HANUMANTHAPPA : Sir, one point has not been made clear. I entirely agree...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Is there a point of order?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It is not a point of order. The Leader of the House has said that the Prime Minister agreed and the Cabinet has taken the first decision. But the Tenth Finance Commission report is there. It is an obligation on the Government. Once you come to that conclusion, you have to go beyond the CRF norms. That has not come out from the Government.

SHRI JASWANT SINGH : Sir, I will clear it. He is quite right. It is a valid enough question. Have we gone beyond the norms? The norm as per the Finance Commission is that the State shall establish a Calamity Relief Fund to which the Central Government will contribute 75 per cent. The State had no Calamity Relief Fund. The State of Orissa has no Calamity Relief Fund. The Rs.500 crores that have already been provided as grant has gone beyond all stated norms in this regard. Please let that be clear. On the question of

terminology, on the question of action taken by the Central Government, on the question of financial assistance, the Central Government has done all that it could, beyond the stated norms.

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपसभाध्यक्ष जी, वहां पर जो कार्य अभी होना है, उसके दो भाग हैं । एक तो मध्यकालीन काम जो वहां पर होना जरूरी है, वह मुख्यतया खेती से शुरू होना है । लेकिन, वहां खेती का काम शुरू करने के पहले जो नमक पानी खेत में फंसा है, उसको एक तो कम करना है, एक मायने में पूरे तौर पर हटा देना है । अब केवल उसी से ही बात नहीं बनेगी क्योंकि जैसा सभी जानते हैं, जानवर तो वहां मर चुके हैं, जिनके आंकड़ों पर कई प्रकार के विवाद हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का मानना है कि 4,44,000 जानवर मर चुके हैं, जिसमें गाय, भैंस, बैल सब आ जाते हैं । तो आज के दिन वहां खेती का काम शुरू करने के पहले अन्य प्रदेशों से बैल भेजने का प्रयास करना होगा, उस दिशा में प्रयास जारी है और फिर या तो पावर टिलर की इंतजामी करनी होगी उसकी इंतजामी करने का कार्य भी जारी है । हमें विश्वास है कि रबी की बुआई जो वहां पर होनी है, हम यह नहीं कह सकते कि संपूर्ण इलाके में हो पाएगी, लेकिन काफी जगहों पर यह कार्य होगा । उसके लिए केन्द्र सरकार से जो मदद पहुंचानी जरूरी है, वह मदद पहुंचाई जा रही है । अभी मंत्री जी इस विषय पर बोलेंगे ही, उनकी तरफ से इसकी विस्तार में जानकारी आपको मिल जाएगी, मगर जो हमको शुरूआत करनी है वह इसी को लेकर करनी है ।

उपसभाध्यक्ष जी, इस तरह के हादसों से बचने के लिए दीर्घकालीन हम क्या कदम उठाना चाहते हैं, यह प्रश्न यहां पर उठाया गया । सबसे पहले हमें लक्ष्य देना है लोगों की जान बचाने पर और जो अभी तक अनुभव रहा है, चाहे आंध्र प्रदेश का हो या तमिलनाडु में कुछ मात्रा में रहा और उड़ीसा का, विशेषकर इस बार का, इससे एक बात स्पष्ट है कि वहां पर जिस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं वह मकान ऐसे तूफान या ऐसी बाढ़ से बच नहीं सकते । इसलिए हम लोगों की जो टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई उसमें यह तय किया गया कि जो मकान अब वहां बनाए जाएंगे या जो गांव फिर बसाए जाएंगे, वहां मकान बनाते समय उस मकान का एक कमरा सीमेंट कंकरीट का बनाना होगा और ऐसे सीमेंट कंकरीट का ताकि जिस प्रकार के वहां हादसे हुए ऐसे हादसों से लोगों को उसमें बचाया जा सके । फिर चाहे उसके साथ जोड़कर व्यक्ति अपने मकान को जिस रूप से बढ़ाना चाहे या एक दो कमरे और बनाना चाहे वह बना सकता है । लेकिन, जो मकान बनाकर दिया जाएगा, उसमें एक कमरा सीमेंट कंकरीट का होगा, जिसमें कि वह खुद को बचाने के साथ साथ अपने जानवरों को बचाने की कोशिश कर पाएगा ।

उपसभाध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश का हमें अनुभव हुआ, वहां ऐसे बड़े मकान बनाए गए हैं,

जिसमें ऐसे मौकों पर लोगों को पहुंचाया जाता है और वहां पर उनके ठहराने का इंतजाम किया जाता है । इस बार एक अनुभव यह हुआ, उपसभाध्यक्ष जी, कि जब पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमेन को सूचना मिली 28 तारीख को, तो उन्होंने कोशिश चलाई लोगों को वहां से दूर ले जाने की और इस तरह हजारों लोगों की जान उन्होंने बचाई, मगर जब हम वहां एक तारीख को पहुंचे तो उन्होंने हमसे बहुत ही दर्द से कहा कि जो दूर नहीं गए, जिन्होंने हमारी बात को नहीं माना, वह सब पानी में बह गए यानि लोग अपना घर छोड़कर जाना पसंद नहीं करते और घर छोड़कर अगर जाने की नौबत आ गई, अकेले जाएंगे, अपने बाल-बच्चों को ले जाएंगे लेकिन अपने घर के जानवरों को छोड़कर जाएंगे तो बात वहीं खत्म हो जाती है । तो इसलिए मकान के बारे में सोची हुई यह बात है और यह केवल मकान तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के स्कूल-कॉलेज लगभग वहां पर उसी हालत में चले गए, जैसे मकान चले गए हैं और जो बचे हैं उनमें आज स्कूल चलाना संभव नहीं है और यह कार्य भी उसी रूप से कि सीमेंट कंक्रीट के मकान, अस्पताल, स्कूल होने चाहिए, इन सारी चीजों का निर्णय लिया गया है और उस दिशा में हुडको ने भी, उनका काम अपने ढंग से चलता है, लेकिन उन्होंने भी इस दिशा में काफी पैसे का आबंटन अभी किया है ।

एक और बड़ी समस्या अभी आने वाली है और यह समस्या महाराष्ट्र सरकार के लोगों ने, जिन्होंने लातूर के भूकम्प में काम किया था, उन लोगों ने मुझे बताई, उन अधिकारियों ने मुझे बताई कि ऐसे हादसे के बाद जब कि परिवार के लोग मारे जाते हैं, कोई एक आधा आदमी बच जाता है और नज़दीक के अपने घर के लोग चले जाते हैं और अकेलापन आ जाता है, तब उस ट्रोमा से जो स्ट्रेस निर्माण होता है उससे आदमी एक हिंसा की ओर जाता है या उसके दिमाग पर असर पड़ जाता है और तीन महीने के बाद इस कार्य में लगना होगा और इसके लिए डाक्टरों को बाहर से वहां पर पहुंचाना होगा और हम इस काम में लगे हैं कि जहां-जहां से हम इसके लिए डाक्टर जुटा सकते हैं उनको जुटाकर वहां इंतजाम किया जाए क्योंकि इतना बड़ा भौगोलिक वह इलाका है, किसी एक जगह पर, राजधानी में या जिला मुख्यालय तक ही जाने की बात नहीं है, लोगों को खोजने जाना होगा या उनको पकड़कर लाना होगा और सांत्वना देने का कार्य, साइक्लोजिकल सांत्वना देने का कार्य करना होगा जो यह डाक्टर लोग कर पाएंगे और उस दिशा में भी जो कदम उठाने होंगे, उठाए जाएंगे । सारे उद्योग इस इलाके के नष्ट हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, मशीनरी खराब हो गई, कर्मचारी चले गए आदि-आदि समस्याएं हैं लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस, जो भी उद्योग वहां पर हो, छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, उनके लिए इंश्योरेंस का जो भी

पहले अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितनी हानि हुई है, वह अंदाज़ा तत्काल लगाकर उनको इंश्योरेंस का पैसा दिया जाना चाहिए । इसके साथ ही साथ बैंकों को आदेश दिया गया और उन्होंने यह कार्य शुरू कर दिया है कि बैंकों के ज़रिए उनको तत्काल अपना उद्योग-धंधा शुरू करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है, वह पूंजी दी जानी चाहिए और ये दोनों काम शुरू हुए काफी दिन हो गए और जैसे-जैसे पानी निकलता चला गया, वैसे-वैसे यह काम चलता रहा और हमें विश्वास है कि जल्दी ही उनमें से अधिकतम उद्योगों को फिर से खड़ा करने में हमें कामयाबी मिलेगी और रोज़गार का जो एक बड़ा प्रश्न है, खेती और उद्योग, इन दोनों के ज़रिए रोज़गार की समस्या को हल करने का कार्य भी किया जाएगा ।

SHRI NILOTPAL BASU: Who will provide the money? Will the GIC do the work of providing the money?

SHRI GEORGE FERNANDES: The banks and the insurance companies; both have accepted the responsibility. They have been given specific directions.

SHRI JIBON ROY: Even the private banks are doing that.

SHRI GEORGE FERNANDES: The lead bank of the State has taken the responsibility, responsibility, but other banks also have been directed by the Reserve Bank.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Have you directed the private banks? Or, have you directed only the nationalised banks?

SHRI GEORGE FERNANDES : If my understanding is correct, then it has been only to the nationalised banks.

SHRI JIBON ROY : Sir, what about the private sector banks?

SHRI GEORGE FERNANDES : I am sorry.

SHRI JIBON ROY : You please see to it that the private banks also are directed accordingly.

SHRI GEORGE FERNANDES : We will take note of that If the private sector banks are operating, then alone the question of giving a direction will arise. If the private sector banks are not operating, then I don't think they can direct.

SHRI JIBON ROY : In Bhubaneshwar, there are private banks.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Kindly see to it that they also fall in line.

SHRI GEORGE FERNANDES : It is fair enough, if they are there then they will fall in line. They have to fall in line. उपसभाध्यक्ष महोदय, रोज़गार का जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए एक तरफ खेती और दूसरी तरफ उद्योग-धंधो की तरफ ध्यान देना होगा । ये दीर्घकालीन चीजे तैयार करने का जो कार्य है, वह जिम्मेदारी भी टास्क-फोर्स पर प्रधानमंत्री ने डाली है । उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वे इस प्रकार है - (a) Prepare a comprehensive action plan of rehabilitation and reconstruction in the cyclone affected areas of Orissa, which should include both short-term, medium-term, and long-term measures.

(b) Make recommendations regarding the mode of implementation of the plan, including its funding, participation of governmental as well as non-governmental organisations etc.

(c) Make recommendations regarding the steps that need to be taken in other areas of the country which are prone to such calamities.

महोदय, यह जो बात बार-बार यहां पर माननीय सदस्यों ने छेड़ी कि अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं निकाला गया है जो ऐसी आपदा के समय तत्काल काम में लाया जा सके । यह बात सही है और यह कार्य होना जरूरी है और केवल उड़ीसा तक ही यह सीमित नहीं है । उड़ीसा का अनुभव, आंध्र का अनुभव, इन सारे अनुभवों को मद्देनज़र रखकर भविष्य में ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे, यह तय करने का कार्य इस टास्क-फोर्स पर ही डाला गया है और इस दिशा में हमारा कार्य जारी है और इसकी रिपोर्ट हम शीघ्र ही प्रधानमंत्री को देंगे । मैं और समय नहीं लेना चाहता हूं

महोदय, मुझे अफसोस है कि हमने जो बातें रखी हैं, उनको लेकर हमारे कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति हुई लेकिन हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उड़ीसा का जो हादसा है, इस के लिए देश के भीतर और देश के बाहर से विभिन्न संस्थाओं से पैसे मिलते रहेंगे, सरकारें अपने ढंग से काम करती रहेंगी लेकिन समूचे देश में अगर इस भाव का निर्माण नहीं होता है कि यह सही मायने में एक राष्ट्रीय हादसा है । समूचे देश को उड़ीसा की ओर जाना है । अगर सारे देश को हम इस कार्य के लिए खड़ा नहीं कर पाए तो हम लोगों का काम कितना भी तेज हो, यह सीमित बना रह जाएगा । हमारी यह प्रार्थना है कि चाहे अन्य कोई भी विवाद हम लोगों के बीच में हों लेकिन उड़ीसा को फिर

से बनाने के लिए, फिर से एक नए उड़ीसा का निर्माण करने के लिए सारे देश के लोगों का हम आह्वान करते हैं ।

SHRI JIBON ROY : How much money has been contributed by the people to the Prime Minister's Relief Fund on account of Orissa?

SHRI GEORGE FERNANDES : Are you talking about the Relief Fund?

SHRI JIBON ROY: How much money has come from the people ....*(Interruptions)*... Altogether, how much money has come from the people and the States? ....*(Interruptions)*....

SHRI GEORGE FERNANDES : The money has by and large gone to the State Government. The money has not come....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU : What is the response of the people? How much money has come to the Prime Minister's Relief Fund? ....*(Interruptions)*.... Our understanding is that there has been an excellent response. ....*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : In Tamil Nadu, the Chief Minister, Mr. Kalaignar, has sent Rs. 50 lakhs cash. Cloth, food and other things to the extent of Rs. 5 crores have been sent. ....*(Interruptions)*... What I want to say is that we have given it not to the Centre, but we have given it directly to the State. ....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU : Many States have done that. That is not the question. ....*(Interruptions)*.... How much money has been collected in the Prime Minister's Relief Fund?....*(Interruptions)*... That would give us an indication.....*(Interruptions)*...

श्री जार्ज फर्नान्डीज: उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि प्राईम-मिनिस्टर रिलीफ फंड को जो पैसा जाता है, वह एक स्पैसिफिक कारण बताकर नहीं जाता है । आम तौर पर प्राईम-मिनिस्टर रिलीफ फंड को पैसा जाता है और अगर कोई यह कहकर दे कि इस अमुक कार्य के लिए हम दे रहे हैं तो बात अलग है लेकिन आम तौर से इस तरह से पैसा नहीं जाता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : It is disbursed for a particular cause.

SHRI JIBON ROY: Sir, there is one point. What is the total amount? A call is given for contribution. The Chief Ministers of various States, the Prime Minister and the people are responding to it. If people do not know what the total effect of this effort is, the people cannot be enthused. I request the Government to find out how much money has come for providing relief to the people of Orissa from various fronts. What is the total contribution of the people?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: If you open an escrow account, we can know.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Sir, may I put one question to you? Last year, I had requested for a discussion on environmental degradation. A caution was sounded about deforestation. We are quoting disasters like cyclone. The cyclone is hitting the interior parts of the country because of the absence of mangroves or forest cover. Could your Task Force also consider this long-term measure to prevent the extent of the calamity? Prevention is not always possible, but we can minimise the gravity and severity of such cyclones. Could you kindly consider it? You don't answer now. I request you to consider it.

SHRI GEORGE FERNANDES : Sir, it has been appreciated that one of the factors which caused this great tragedy is the fact that the Orissa coast is not protected by mangroves, which we have in the west coast. We don't have that here. Therefore, in the course of our discussion, this issue can be taken up.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : This should be taken up on a war-footing. Mr. Nitish Kumar.

श्री नीतीश कुमार : उपसभाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री जी जो इस संबंध में बनाए गए हाई पावर्ड टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, उनके और सदन के नेता और विदेश मंत्री जी की इस चर्चा में हस्तक्षेप के बाद औपचारिक उत्तर की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है । सिर्फ दो-तीन बातों का उल्लेख करना है कि इन्होंने कृषि संबंधी कुछ मामलों को छोड़ दिया है । यहां चर्चा के दौरान यह शंका जाहिर की गई थी कि सेलेनिटी को लेकर इसके बारे में दूसरे सदन में भी चर्चा हुई थी तो उसका उत्तर देना पड़ा था । इस साइक्लोन से जो पूरा क्रॉप एरिया अफेक्टेड है, वह 17.11 लाख हेक्टेयर है और रबी क्रॉपिंग प्रोग्राम में हम यह उम्मीद करते हैं कि 9.38 लाख हेक्टेयर कवर किया जा सकेगा । जहां तक सेलेनिटी का सवाल है, इसके बारे में जो जांच-पड़ताल शुरू में की गई, उसके हिसाब से यह उसके

लिए उतनी भयानक स्थिति नहीं है और ज्यादातर जगहों पर जो सेलेनिटी का लेवल है, वह लिमिट के अंदर है । इसलिए वहां रबी क्रॉप ली जा सकेगी । यही कारण है कि इतने बड़े एरिया में, 17 लाख हेक्टेयर में अगर यह बरबादी हुई है तो 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा ज़मीन पर रबी की फसल ली जा सकेगी । कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं खासकर आस्मा ब्लॉक में जो अंदाज़ लगाया जा रहा है कि लगभग 20 हज़ार हेक्टेयर है, उसको अलग से टैकल करना पड़ेगा । बीज आदि की भी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी । जो कुछ भी वहां से कहा जा रहा है अलग-अलग क्रॉप्स के लिए उनका सोर्स भी उनको बताया जा रहा है और जो भी इस संबंध में अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो मदद जा सकती है, वह भी जा रही है । राज्य सरकार को उस दिशा में आगे कदम बढ़ाना है । कैटल फीड के बारे में भी यही बात है, वह सीधे मदद नहीं मांग रहे हैं । उनको आइडेंटिफाई करना था सोर्सेज के बारे में, वह सब किया जा चुका है और उस पर तेज़ी से कार्यवाही हो रही है । जहां तक साइक्लोन आने से पहले, जिसकी कुछ बातों का उल्लेख रक्षा मंत्री जी ने यहां किया है और साइक्लोन आने के बाद जो कुछ भी तय किया गया है, सब बातों का उल्लेख यहां नहीं किया गया है और समय की कमी के कारण संभव भी नहीं है । इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, पूरी स्थिति की जानकारी एक पत्र के ज़रिए मैं सभी माननीय सदस्यों को दे दूंगा, जो कुछ भी किया गया, अलग-अलग हेड में क्या किया जा रहा है, अलग-अलग प्रोग्राम्स में क्या किया जा रहा है, आगे क्या योजना बनी है, टास्क फोर्स भी बैठकर अब तक क्या प्रगति कर सका है, इन सब चीज़ों की जानकारी एक-दो दिन के अंदर पत्र के ज़रिए, विस्तृत जानकारी हम दे देंगे ताकि लोग अपने स्तर से भी सुझाव दे सकें । सरकार को भी, टास्क फोर्स को भी तथा जो लॉंग टर्म मेज़र्स लिए जा रहे हैं, रीकंस्ट्रक्शन के जो प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, उसमें वे कुछ बताना चाहेंगे तो उनको सहूलियत हो जाएगी ।

एक सवाल ऐसा आया जिसकी चर्चा की गई, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में । मुझे जो जानकारी दी गई है, वह यह है कि यह एक ट्रस्ट है और इससे संबंधित मामलों की चर्चा संसद में नहीं की जाती है, इस पर चर्चा नहीं होती है । उसके बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध थी वह उन्होंने दे दी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता प्रकट की है, वह सबकी समान चिन्ता है और हर हालत में इससे राष्ट्रीय स्तर पर हमें निपटना है। उसके लिए जो भी जरूरी कदम हैं वे उठाये जा रहे हैं और इसमें पूरा राष्ट्र एक है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए , जितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं।